Agro-Climate Specific Research

645. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the agricultural scientists are working on agro-climate specific research for developing tubuologies to enhance agricultural production in the country;

(b) if so, the success achieved by them with the improved management in the productivity; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) No, Sir. No agro-climate specific research for developing "tubuologies" is being carried out by agricultural scientists.

(b) Question does not arise.

(c) Question does not arise.

गुजरात और मध्य प्रदेश में खनन हेतु अनुमति

646. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः क्या खान मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे किः

(क) कितने आदिवासी लोगों, बहुराष्ट्रिक कंपनियों और देश के गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में, खनन कार्य शुरू करने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितनी कंपनियों को मध्य प्रदेश के महासमुन्द और छत्तीसगढ़ क्षेत्र तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खनन के लिए अनुमति प्रदान की गई है तथा इस संबंध में किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

 (ग) इन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। (झी गिरधर गमंग): (क) खान और खतिजों (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत खनन अधिकार, कम्पनी अधिनियम 1956 की घारा 3 की उप घारा (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक या कम्पनी को दिए जा सकते हैं। पट्टा देने के संबंध में किसी कम्पनी के स्वामित्व अथवा किसी व्यक्ति को जाति/धर्म प्रासंगिक कारक नहीं हैं। अतः इन श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आठवीं पचंचर्षीय योजना के दौरान इस्पात क्षेत्र का विकास

647. भी कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोलाः क्य इस्पात मंत्री यह बताने की कपा करेंगे किः

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर किननी राशि खर्च की जाएगी;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय क्रोअना के दौरान इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

 (भ) यदि हां, तो उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विदेशी सहायता भी मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (झी सन्तोष मोइन देव): (क) और (ख) सरकार ने इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) हेतु 774.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 14579.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मन्जुर किया है।

(ग) और (ध) नौंवी पंचवर्षीय बोबना के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्य और परिव्यय निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है।

(क) और (च) उपयोक्त (ग) और (घ) को मन्द्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।